# RAJYA SABHA

*Thursday, the 16th July, 1992/ 25th Asadha, 1914 (Saka).*

The House met at eleven of the clock.

**The Deputy Chairman** in the Chair.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Enforcement of the Supreme Court Judgement

### Regarding Provident Fund in Beedi and Cigar Industries

*121. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL:†
DR. BAPU KALDATE:

Will the PRIME MINISER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have failed to enforce the Provident Fund Act in the Beedi and Cigar industries where according to a rough estimate, about 40 lakh workers are still awaiting implementation of the Supreme Court judgement given 7 years back as per the news-item captioned 'Beedi, Cigar Industry: Government failure on P. F. front, which appeared in the 'Hindustan Times' dater the 19th June, 1992;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) what remedial steps Government have taken or propose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) to (c) A statement is liad on the Table of the House.

### Statement

The provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 were extended to the Beedi Industry with effect from 1-6-1977. The majority of the Beedi manufacturers did not, however, implement the Act and challenged its applicability in the Supreme Court. The Supreme Court, in its judgement delivered in September, 1985 upheld the applicability of the EPF Act to the Beedi industry. Consequent to the judgement of the Supreme Court, necessary steps were taken by the EPF authorities to secure compliance under the EPF Act from the Beedi industry.

Under the EPF & MP Act all establishments which are in existence for more than 3 years and are employing more than 20 workers are coverable. As per the latest figures available, about 12 lakhs beedi workers stand enrolled as members of Provident Fund. The number of PF subscribers in cigar industry at present is 27,745.

**श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** मैडम, जो जवाब आया है वह जिवाब पहले ही अखबारों में छप चुका है, कोई इसमें नई खास बात मंत्री जी ने नहीं बताई है और मैंने अपना सवाल करते हुए "हिंदुस्तान टाइम्स" को बकायदा रेफर किया था । मुझ को लगता है कि उस कटिंग को भी नहीं देखा गया कि मसला क्या उठाया गया है ।

मैडम, हिंदुस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, जिनकी आमदनी 5 रूपए, 4 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 10 रुपए और 12 रुपए तक है पर डे । ये लोग बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं । सन 1977 के अंदर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया भी है, एक कोर्ट का जजमैन्ट था जिसमें कहा गया है कि प्रोविडेंट फण्ड को लागू किया जाए । उसके बाद आज तक इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है । फिर सन् 1985 के अंदर दुबारा से जब सुप्रीम-कोर्ट गए मैनुफेक्चरर इसको लेकर ताकि प्रोविडेंट फंड न दिया जा सके तो सुप्रीम-कोर्ट ने भी उस जजमेंट को बाकी रखा और मजदूरों को प्रोविडेंट फंड देने के लिए कहा, लेकिन आज तक इतलाख नहीं हुआ । मेरी जानकारी के मुताबिक जो मैनुफेक्चरर हैं और प्रोविडेंट फंड के जिम्मेदार लोग

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Mohammed Afzal alias Meen Afzal.

हैं, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपस में मिले हुए हैं। अब तक, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, 12 लाख बीड़ी वर्कर एनरोल हैं और 27,745 सिगार मजदूर जो ये हैं एनरोल हैं।

मैडम, मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से, कि क्या जो फिगर आपने दी है, उतनी ही फिगर मुल्क के अंदर है? और, अगर यह फिगर ज्यादा है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, 40, 50 लाख से ज्यादा है तो उन पर प्रोविडेंट फंड स्कीम को लागू करने में क्या परेशानी है, जबकि, दो मजदूरों से ज्यादा किसी फैक्टरी में काम कर रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड का रूल लागू होता है?

ایک کورٹ کا ججمنٹ تھا جس میں کہا گیا ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو لاگو کیا جائے۔ اس کے بعد آج تک اس پر پوری طرح سے عمل نہیں ہوا ہے۔ پھر سنہ ۱۹۸۵ء کے اندر دوبارہ سے جب سپریم کورٹ گئے۔ مینوفیکچررس کو لیکر تاکہ پراویڈنٹ فنڈ نہ دیا جاسکے

تو سپریم کورٹ نے بھی اس ججمنٹ کو باقی رکھا اور مزدوروں کو پراویڈنٹ دینے کیلئے کہا لیکن آج تک اطلاق نہیں ہوا میری جانکاری کے مطابق جو مینوفیکچرر ہیں اور پراویڈنٹ فنڈ کے ذمہ دار لوگ ہیں۔

یہ لوگ ہر طرح سے چار کر رہے ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب تک جیسا کہ منتری جی نے بتایا۔ ۱۲ لاکھ بیڑی ورکر اینرول ہیں اور ۲۷۷۴۵ سگار مزدور جو ہیں اینرول ہیں

میڈم۔ میں پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں منتری جی سے کہ کیا جو فیگر آپ نے دی ہیں۔ اتنی فیگر ملک کے اندر ہیں اور اگر یہ فیگر زیادہ ہیں۔ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ چالیس پچاس لاکھ سے زیادہ ہیں تو ان پر پراویڈنٹ فنڈ اسکیم لاگو کرنے میں کیا پریشانی ہے۔ جبکہ دو مزدوروں سے زیادہ کسی فیکٹری میں کر رہے ہیں تو پراویڈنٹ فنڈ کا رول لاگو ہوتا ہے۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل، میڈم جو جواب آیا ہے وہ جواب پہلے ہی اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ کوئی نئی خاص بات منتری جی نے نہیں بتائی ہے اور میں نے اپنا سوال کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمس کو باقاعدہ ریفر کیا تھا۔ مجھ کو لگتا ہے کہ اس کٹنگ کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ مسئلہ کیا اٹھایا گیا ہے۔

میڈم۔ ہندوستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق ۵۰ لاکھ مزدور کام کر رہے ہیں جن کی آمدنی پانچ روپے سے دس روپے اور بارہ روپے تک ہے پڑتی ہے۔ یہ لوگ بہت ہی بری حالت میں رہتے ہیں۔ ۱۹۷۷ء کے اندر جیسا کہ منتری نے بتایا بھی ہے

†[] Transliteration in Arabic Script.

**उपसभापति :** जरा अगर आप क्वैश्चन को छोटा कर लें तो आपको जानकारी थोड़ी वे दे देंगे ।

**श्री प्रमोद महाजन :** सुप्रीम-कोर्ट के फैसले पर आ गए हैं ... **(व्यवधान)**

**श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** नहीं, वे तो कह रहे हैं, सुप्रीम-कोर्ट के फैसले पर अमल कर रहे हैं । यह 12 लाख जो मजदूर एनरोल किए गए हैं, मेरा कहना यह है कि 12 लाख मजदूर नहीं हैं एक्चुअली । फिर सात साल से उसको भी इन्होंने पूरी तरह से लागू नहीं किया है । तो उसकी क्या वजह है ?

†شری محمد افضل عرف م۔ افضل: نہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ بارہ لاکھ جو مزدور اینرول کئے گئے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بارہ لاکھ مزدور نہیں ہے ایکچولی پھر سات سال سے اس کو بھی انہوں نے پوری طرح سے لاگو نہیں کیا ہے تو اس کی کیا وجہ۔

**डा० बापू कालदाते :** तो इलाहाबाद या क्यों ? ... **(व्यवधान)** ...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Madam, referring to the newspaper report, the honourable Member has said that I have not seen that report. I have very much seen the report. Not only have I seen the report. but also I have read it and a copy of it is with me. So, I am aware of the newspaper reports.

Madam, it is true that the total number of beedi workers is estimated at 44 lakhs and that is the estimated number. Out of the 44 lakhs of beedi workers, 24 lakh workers have been issued with identity cards. So, we know the whereabouts of the 24 lakh workers. To the rest we have not been able to issue the identity cards since they are working in their homes and remote areas. I admit, we have not been able to identify them and bring them under the Provident Fund Scheme. But at point arises here. Since we have identfied 24 lakhs, then we should have been able to cover all the 24 lakh workers under the Provident Fund Scheme. That argument is very valid. But only 12 lakhs have been covered. Out of the 24 lakhs, seven lakhs workers belong to the Eastern Region of India, that is, Bihar, West Bengal and Orissa. Madam, in spite of the Supreme Court judgment on the 25th September, 1985, some people have gone to the Calcutta High Court, and there are as many as 20 cases pending in the Calcutta High Court with a stay order that the Provident Fund Act provisions should not be extended to them. Therefore, out of 24 lakhs, 7 lakhs have already gone. That means, 7 plus 12, 19 lakhs are already covered. Under the Provident Fund Act, it is is only in places where the workers are 20 or more that the Provident Fund Act can come into operation. Secondly, those who are above 55 years of age are not covered under the Provident Fund. Most of the Bedi workers are home workers—there are a large number of them who are above 55 years of age. These are the reasons why we are not able to cover the entire number. But we are making every effort to see that a large number of Beedi workers are covered under the Provident Fund Act.

**उपसभापति :** सैकिंड सप्लीमेंटरी ।

**श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** मैडम, मंत्री जी ने यह बिल्कुल सही बताया और मुझे खुशी हुई जो जानकारी उन्होंने दी है । लेकिन क्या यह बात हकीकत नहीं है कि जो बीड़ी मजदूर हैं उनसे जानबूझकर घरों पर इसलिए काम कराया जाता है ताकि वह बाकायदा

†[] Transliteration in Arabic Script.

एनरोल न किए जायें। ऐसा मैन्युफैक्चरर्स जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि उनको प्रोविडेंट फंड का आधा हिस्सा न देना पड़े। अगर 77 के हिसाब से अखबार ने जो कुछ कैलकुलेट किया है, वर्ष तकरीबन पांच सौ करोड़ रुपया गरीब मलदूरों का जो प्रोविडेंट फंड में उनको मिलना चाहिए था, , वह मैन्यूफैक्चरर्स ने मार लिया। जो 20 पैंडिंग कोर्ट की बात कही है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट में जो लोग चले गए हैं मैं उनका ज्यादा चिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि मामला सब-ज्यूडिस है। लेकिन क्या सरकार ऐसा कोई बंदोबस्त करेगी कि जो लोग घरों पर काम कर रहे हैं और जानबूझकर जिनसे घरों पर काम कराया जाता है तथा फैक्टरी में नहीं कराया जाता और वह मजदूर सुबह को आते हैं और आपने 50–55 साल से ऊपर के लोगों को कहा है, ऐसे भी बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं वह भी पजारों लाखों की तादाद में बीडी मजदूरों का काम कर रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है या सरकार कोई ऐसा काम करेगी कि जाकर के यह मालूम किया जाय कि जिन ओनर्स के यहां से मजदूर सुबह को काम ले जाते हैं और शाम को लाकर के देते हैं, उनको सकायदा आइडेंटी कार्ड इश्यू किए जाएं और उनके प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन किया जाय।

श्री मोहम्मद अफजल (उर्दू)। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस सवाल पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो बड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है या सरकार कोई ऐसा काम करेगी कि जाकर के यह मालूम किया जाय कि जिन ओनर्स के यहां से मजदूर सुबह को काम ले जाते हैं और शाम को लाकर के देते हैं, उनको बाकायदा आइडेंटी कार्ड इश्यू किए जाएं और उनके प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन किया जाय।

†श्री मोहम्मद अफजल (उर्दू)। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस सवाल पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो बड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है या सरकार कोई ऐसा काम करेगी कि जाकर के यह मालूम किया जाय कि जिन ओनर्स के यहां से मजदूर सुबह को काम ले जाते हैं और शाम को लाकर के देते हैं, उनको बाकायदा आइडेंटी कार्ड इश्यू किए जाएं और उनके प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन किया जाय।

†[] Transliteration in Arabic Script.

**उपसभापति** : महिलायें ।

**श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** हां, महिलायें भी हैं ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : ہاں مہلائیں بھی ہیں ۔

**श्री संघ प्रिय गौतम** : सात साल से वायदा कर रहा है सुप्रीम-कोर्ट के आदेशों का ।

SHRI P. A. SANGMA: Thank you, Madam, for reminding me. Madam, I have already answered that question. Out of 44 lakh Beedi workers in our country, it is only 1-70,000 who are working in a factory where all the provisions of law can be applied to them, and there is no difficulty. But the maximum of them are working at home as home workers.

SHRI JAGESH DESAI: 95 per cent.

SHRI P. A. SANGMA: Yes, 95 per cent are home workers which includes people above 55 years and below 18 years —children are also working, So, it is not an easy job. Therefore, we are trying our best, and progressively we are doing that. At the time of the Supreme Court judgment, that is on the 25th September, 1985, the total number of Beedi workers covered under the Provident Fund was only 5 lakhs, slightly less than 5 lakhs, four point or something. But from that time onwards, we have now reahced 12 lakhs. That means, we have added quite a number. So, we are progressively going towards that.

**श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : मैडम, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ है ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : میڈم میرے سوال کا جواب نہیں ہوا ہے ۔

**उपसभापति** : कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए ।

**श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : मैंने यह पूछा है, खुद मंत्री जी ने कुबूल किया है कि 24 लाख को आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी 20 लाख को नहीं कर सके हैं । तो मेरा कहना यह है कि उन 20 लाख वर्कर्स को आइडेंटिफाई करने का और उनका प्रोविडेंट फंड लागू करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी ?

شری محمد افضل عرف م۔ افضل : میں نے یہ پوچھا ہے۔ خود منتری جی نے قبول کیا ہے۔ کہ ۲۴ لاکھ کو آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے باقی ۲۰ لاکھ کو نہیں کر سکے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان ۲۰ لاکھ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کا اور ان کا پراویڈنٹ فنڈ لاگو کرنے کے لئے سرکار کوئی قدم اٹھائے گی۔

**उपसभापति** : डा० बापू कालदाते । वह कम्बाइंड जवाब देंगे ।

**डा० बापू कालदाते** : उपसभापति जी, आपके जवाब से जो दो-तीन सवाल उठते हैं वही पूछूंगा । आप खुद कह रहे हैं कि जो आइडेंटिफाई करना चाहिए वह अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहु अधिकांश लोग पत्ते लेकर घर जाते हैं और फिर वहां बीडी बनाते हैं । तो अगर आपको यह करना है, आपने जो खुद लिखा है पैरा नं० 2 में ।

"Under the EPF & MP Act, all establishments which are in evistence for more than 3 years and are employing more than 20 workers are coverable."

†[ ] Transleteration in Arabic script.

अगर यह बात आप करें कि हरेक मजदूर जो जाता है उसको आप एक आईडेंटिटी कार्ड दे दें तो वह भले ही घर में काम करे या एक साथ काम करे, शैल्टर में काम करे, मैं संगम नेर, अकोला, औरंगाबाद, जालना के बीड़ी मजदूरों के बारे में जानता हूं। ये लोग सामान लेकर जाते हैं और देहात में काम करते हैं। महाराष्ट्र की हद तक बात मैं कहता हूं। ये लोग गांव में जाकर काम करते हैं। अगर यही आपका 20 वर्कर्स वाला मामला रहेगा तो यह संभव नहीं होगा और आप कैसे इन लोगों को प्राविडेंट फंड की मदद कर सकेंगे? तो क्या आप यह 20 वाले को हटाकर, जो आईडेंटिटी कार्ड वाला कोई भी होगा, उसको आप प्रॉविडेंट फंड के अंदर लाने का प्रयास करेंगे?

दूसरा, आपने यह कहा है कि "3 साल से पुराने"। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने 3 साल पुराने वाली बात कही है, यह किस साल की है? यानी यह जो आपने लागू करने का प्रयास किया है ६ साल वाला, तो कौन से साल से शुरू हुआ? जिस साल शुरू हुआ, तब से अब तक क्या सरकार को मालूम है कि कितना प्रॉविडेंट फंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने सरकार के पास रख दिया है, उसकी कुछ जानकारी देंगे। उसमें इतना लिखा गया है कि इतने वर्कर्स हैं तो कितना प्रॉविडेंट फंड इन सालों में इन गरीबों का जमा है, इसकी जानकारी आप दे दें तो लगे कि सरकार किस दिशा में जा रही है। आप कह रहे हैं कि आवश्यक प्रयास कर रहे और एवरीथिंग पॉसिबल, तो क्या पॉसिबल कर रहे हैं इसका भी थोड़ा हम लोगों को पता लगे।

SHRI P. A. SANGMA: Most of the points made by the hon. Member are valid. I agree that the only way to implement the decision of the Supreme Court is to identify the workers. Now, so far, we have identified 25 lakhs. The responsibility of identifying the beedi workers would rest with the respective State Governments and they are trying their best. We also thought that we should leave this matter only to the State Governments. So, recently we have issued instruction that our Welfare Commissioner will also now start issuing identity cards. That is the progress we have made and we are progressively moving towards that.

The second part of the question is about applying the Act in case of home workers where the number is 20 or less than 20. I am inclined to agree with the hon. member. But there could be a way found out to overcome the problem because in the beedi industry, the problem is not only to identify the workers but also after having identified the workers, to establish the relationship between the employer and the employee, because the real employer does not directly deal with the home workers. He gives work to a contractor and it is the contractor who engages people at home. Now if the relationship is between a contractor and the home workers, then we cannot overcome this problem of the number of 20 workers but once we are able to establish the relationship between the employer and the workers, I think this problem can be overcome, and we are trying for it.

DR. BAPU KALDATE: What about the amount of provident fund that the Government has collected? That is also a part of my question.

SHRI P. A. SANGMA: The figure of the entire amount is not available with me. I was more concerned with the amount between 1st of June, 1977 when the Government decided to apply this Act and the date of the Supreme Court's ruling when the Supreme Court said, yes, it is applicable. So, between the 1st of June, 1977 and 25th September, 1985, the amount that we have collected from the workers is Rs. 10 crores. Others are routine things.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: I come from an area where beedi rolling is a major occupation. My father also was a beedi manufacturer 50 years ago. He is no more. I know very much the plight of the beedi workers. Madam, you know that tobacco is how much injurious and hazardous to health. It is injurious whether it is smoked or chewed. In their profession, the beedi workers are constantly in touch with tobacco for the whole day. Tobacco is injurious; Because they are in constant touch with tobacco, the health of the beedi workers is very much affected. Besides, when they are at work, most of their limbs are not in use.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Put your question. Be brief.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: I am putting my question. When they are at work, they use only their fingers and the other limbs are not in use. Most of them become victims of tuberculosis or some other dangerous disease. Therefore, my question to the hon. Minister is, whether the Government will take steps to make the manufacturers, or employers, responsible for a periodical medical check-up for the beedi workers.

SHRI P. A. SANGMA: Madam, the hon. Member's question does not relate to the main question, but...

SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: It may not be related to the provident fund part. But it relates to the welfare of the beedi workers.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is answering.

SHRI P. A. SANGMA: The main question specifically relates to the application of the Provident Fund Act. But the hon. Member wants to know about the other welfare measures for the beedi workers. The beedi workers are working in a very bad condition. I agree with him. Now, we have the Beedi Workers' Welfare Fund. We have the Welfare Commissioner. All kinds of welfare activities are undertaken for the benefit of the beedi workers. I do not have the details of these. We do have a number of schemes. For example, we have a scheme for education. We have a scheme for health care. We have other schemes which benefit the workers. Recently, we have brought out a scheme of group insurance. Under this, a worker will get Rs. 3,000 in the case of a natural death, Rs. 6,000 in the case of a death by accident. The workers are not required to pay anything towards this group insurance scheme.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: My Question is...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is answering.

SHRI P. A. SANGMA: I am voluntarily giving the information. We have 4 hospitals and 154 dispensaries for the beedi workers. I do not have the full information now. If the hon. Member wants, I can supply it to him.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: I wanted to know whether there was any periodical medical check-up.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will find out and let you know.

SHRI SARADA MOHANTY: Madam, in Andhra Pradesh, most of the people use cheroot. I would like to know whether the cheroot workers are covered by the provident fund scheme or not.

SHRI P. A. SANGMA: Madam, I have answered it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has answered this question. (*Interruptions*) ..

श्री मूल चन्द मीना : महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि पी.एफ. का जहां तक सवाल है यह बड़ा महत्वपूर्ण है ।

बीड़ी उद्योग के निर्माता पी.एफ. के नाम पर पैसा तो कर्मचारियों का काट लेते हैं लेकिन न तो उस पैसे को वह जमा कराते हैं और न मजदूर जब मांगते हैं उनको देते हैं, वह अपनी जेब में उस पैसे को रखते हैं।...

**श्री सभापति**: यह सवाल पूछ लिया गया है, कोई नया सवाल है तो पूछिए नहीं तो I will move to another question.

**श्री मूल चन्द मीना**: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं? यदि मिली हैं तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have already answered this question.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Madam, may I know from the hon. Minister what is the percentage of manufacturers implementing this Act? My information is that, even to the extent it is implemented, after retirement, they are harassed. They are not paid the provident fund at all. So far as Andhra Pradesh is concerned, may I know from the hon. Minister how many workers are identified and how many manufacturers are implementing this Act?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think he has answered that also.

SHRI P. A. SANGMA: I have already answered that. The number of establishments is not with me, but the fact remains that out of 44 lakhs only 12 lakhs have been covered under the P.F. Act and we are going progressively to cover others also.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: My question is that even where it is covered they are not paying the dues to the workers after their retirement. They are harassing them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has already answered your question. Yes, Mr. Muthu Mani.

SHRI S. MUTHU MANI: Madam, I learn that interest on provident fund is paid calculating the balance at the beginning of every year. This causes interest loss to the workers, as you know interest is being paid on monthly additions. Will the Government consider payment of interest on monthly basis? Secondly, will the interest rate now being given be increased in view of the inflation?

SHRI P. A. SANGMA: Again this is not related to the main question.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Madam Deputy Chairman, many of the beedi workers are working in homes. Is P.F. also applicable to the home-based Beedi workers? Is there any proposal to cover home-based workers in all other sectors also? I have written to the Labour Ministry to see that a similar legislation is brought for the benefit of home-based workers in different sectors along with beedi workers.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Especially handloom.

SHRI P. A. SANGMA: I have said that out of 12 lakh workers which have been covered under the Provident Fund Act, 1,70,000 are the regular factory workers. Therefore, the remaining 10,30,000 workers are home-based workers. This I have already answered.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 122. (*Interruptions*). Mr. Kotaiah, we have moved from beedi to some other thing.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: What is the use of our putting the questions? He has not been able to answer....

THE DEPUTY CHAIRMAN: If it is not related to the original question, how can he reply to anything under the sun?

Yes, Shrimati Satya Bahin. Next Question.

**Shortage of Medicines**

*122. SHRIMATI SATYA BAHIN:†
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a number of press reports which appeared in June, 1992 about the shortage of medicines;

(b) if so, what is the reaction of Government thereto and what remedial steps have been taken in this regard;

(c) whether it is a fact that producers have deliberately stopped production as the sales turnover is very low despite the fact that the products are price decontrolled:

(d) if so, the names of those products;

(e) whether it is also a fact that producers of products based on imported bulk drugs have stopped production in order to have higher price of bulk drugs than the weighted average price;

(f) if so, the names of such products where higher prices of bulk drugs have been claimed; and

(g) what are the names of producers who are importing bulk drugs from their principals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (g) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) Yes, Sir.

(b) The position of the reported shortages has been analysed. Most of the shortages so reported are of specific brands and of medicines having low turn-over. In most such cases, equivalent medicinns are available in other brands. Government watches and invariably contacts producers of specific brands in order to overcome shortages as and when they are reported in any area of the country.

In some cases such Vitamin C, there were problems in regard to pricing of bulk drugs and formulations which have since been tackled and the situation should normalise soon.

(c) No such instance has come to the notice of the Government.

(d) Does not arise.

(e) No such instance of stoppage of production has come to the notice of the Government.

(f) Does not arise.

(g) Companywise imports/origin of imports are not monitored in this Department.

**श्रीमती सत्या बहिन :** उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने यह स्वीकार किया कि दवाइयों में कमी आई है हालांकि 9 जुलाई को मंत्री महोदय ने यह बताया था कि दवाइयों की कोई शार्टेज नहीं है। पहले तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि 9 जुलाई से अब तक क्या डवलपमेंट हुई हैं? दूसरे ड्रग कंट्रोल 1987 के बाद दवाइयों के मूल्यों में सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है क्या सरकार को इसकी जानकारी है? इसके कारण दवाइयों का उत्पादन भी कम हो गया है और गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है ये दवाइयां और जो दवाइयां मिलती हैं वे भी मनमाने मूल्यों पर मिलती है। मैं जानना चाहती हूं कि इसकी तरफ सरकार का ध्यान है या नहीं?

SHRI CHINTA MOHAN: Madam, what the hon. Member has said is not correct. I have personally gone to various druggists and enquired the position. At present,

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Satya Bahin.